2026:AHC: 22692-DB

निर्णय सुरक्षित :- 20.01.2026

निर्णय पारित :- 03.02.2026

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील संख्या- 2996/2006

जराफत एवं अन्य .....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: हिमांशु रंजन शुक्ला, मनोज सिंह, रमेश कुमार शुक्ला, सदरुल इस्लाम जाफरी, वी.पी. शुक्ला, विवेक कुमार शुक्ला
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: आकाश खरे, शासकीय अधिवक्ता, हरि ओम

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय

1. सी.जे.एम. हापुड़ की आख्या दिनांक 08.05.2025 के अनुसार, अपीलार्थी संख्या 2, फारुख और अपीलार्थी संख्या 3, इखलाक की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए, अपीलार्थी संख्या 2, फारुख और अपीलार्थी संख्या 3, इखलाक के विरुद्ध अपील दिनांक 20.01.2026 को उपशमित के रूप में खारिज कर दी गई है।

2. अपील की सुनवाई केवल जीवित अपीलार्थी संख्या 1, 4 और 5, नामतः जराफत, महबूब और ममनून के संबंध में की गई है।

3. अपीलार्थी संख्या 1, 4 और 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार पाण्डेय; सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री आकाश खरे, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. प्रथम सुश्री मंजू ठाकुर को सुना गया और अभिलेख तथा विचारण न्यायालय के निर्णय का परिशीलन किया गया।

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

4. वर्तमान आपराधिक अपील अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़, गाजियाबाद द्वारा सत्र विचारण संख्या 1429/98 (राज्य बनाम जराफत एवं अन्य) अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 302 भा.द.सं., थाना गढ़मुक्तेश्वर, जिला गाजियाबाद (मुकदमा अपराध संख्या 196 वर्ष 1993) में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 11-05-06 के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थियों को धारा 147 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध करने के लिए एक वर्ष का सश्रम कारावास; धारा 148 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध करने के लिए दो वर्ष का सश्रम कारावास और धारा 302 सहपठित धारा 149 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध करने के लिए आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 10,000/- रुपये के जुर्माने की सजा से दंडादिष्ट किया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

5. अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह है कि 10.06.1993 को दोपहर लगभग 12:30 बजे, सूचनादाता खालिद अपने भाई इश्तियाक के साथ बस से हापुड़ जाने के लिए सड़क पर इंतजार कर रहा था, तभी गाँव के जराफत, फारुख, इखलाक, मारूफ, महबूब और ममनून आए। जराफत और इखलाक के हाथों में लाइसेंसी बंदूकें थीं और अन्य अभियुक्तों के पास देशी तमंचे थे। अभियुक्तों ने कहा कि चलो लताफत की हत्या का बदला इश्तियाक से लेते हैं और फिर उन सभी ने अपने-अपने हथियारों से इश्तियाक पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। इश्तियाक गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। घटना स्थल के पास मंसूर अली का ट्यूबवेल है, जहाँ अकील, खिलाफत और मंसूर अली मौजूद थे और उन्होंने घटना देखा था।

6. इश्तियाक पर गोली चलाने के बाद अभियुक्त घटना स्थल से भाग गए। जब सूचनादाता प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने गया, तब मृतक का शव मौके पर पड़ा था। उसी दिन दोपहर लगभग 02:15 बजे, अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 196 वर्ष 1993, अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 302 भा.द.सं. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। विवेचना की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने धारा 147, 148, 302 सहपठित 149 भा.द.सं. के अंतर्गत उन पर लगाए गए आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग किया।

7. अभियोजन पक्ष के प्रकरण को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन ने पी.डब्ल्यू.-1, खालिद (सूचनादाता); पी.डब्ल्यू.-2, खिलाफत; पी.डब्ल्यू.-3, डॉ. ए.पी. गुप्ता; पी.डब्ल्यू.-4, उप-निरीक्षक सत्यपाल सिंह (विवेचना अधिकारी) और पी.डब्ल्यू.-5, कांस्टेबल गिरीश वर्मा को परीक्षित किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

8. अभियुक्तों के बयान अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष का प्रकरण झूठा है और उन्हें शत्रुता के कारण इस वाद में झूठा फँसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

9. पी.डब्ल्यू.-1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन के प्रकरण को सिद्ध किया और उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पुलिस स्टेशन पर जब्बार ने उनके कहने पर आवेदन लिखा था। उसके बाद उसे उन्हें पढ़कर सुनाया गया और उन्होंने उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे।

10. अपनी जिरह में उन्होंने बताया कि लताफत की हत्या 1992 में हुई थी। उनके घर और अभियुक्तों के घर के बीच 250-300 फीट की दूरी है। घटना स्थल उनके घर से 20-30 कदम की दूरी पर था। लताफत के हत्या के वाद में उनके भाई इश्तियाक के अलावा तीन अन्य अभियुक्तों को फँसाया गया था। लताफत की हत्या के बाद इश्तियाक ने 2-3 माह के लिए अपना गाँव छोड़ दिया था, लेकिन फिर से वहाँ रहने लगा था। उन्होंने आगे बताया कि वह किठौर के मदरसे में पढ़ते हैं और चूंकि उनके रिश्तेदार की शादी थी, इसलिए उन्होंने गुरुवार को मदरसे से छुट्टी ली थी, जबकि सामान्यतः मदरसा शुक्रवार को बंद रहता है। वह हिंदी में अपना नाम लिख सकते हैं और थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ और लिख सकते हैं। जब्बार ने इस वाद की रिपोर्ट लिखा था। जब्बार मंसूर का बेटा है, जो इस वाद में साक्षी भी है। उन्होंने इश्तियाक की हत्या से पहले अभियुक्तों के साथ मंसूर और जब्बार की शत्रुता के बारे में जानकारी होने से इनकार किया। वह अपने भाई इश्तियाक के साथ हापुड़ जा रहे थे, क्योंकि उनके भाई को वहाँ कुछ काम था, जिसे वह नहीं जानते थे। उनका भाई बस पकड़ने के लिए सड़क पार कर चुका था, जबकि वह सड़क के दूसरी तरफ, आम के पेड़ के पास थे, जब घटना हुई थी।

11. आगे की जिरह में, पी.डब्ल्यू.-1 ने बताया कि उनके चार भाई हैं और वीरमपुर में उनके नाना का घर स्थित है, जहाँ 10.06.1993 को शादी होनी थी। सूचनादाता और उनके भाई इश्तियाक को छोड़कर, उनके बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य शादी में शामिल होने गए थे। उन्हें घटना की सूचना उनके घर पर मिली, लेकिन उन्हें याद नहीं कि सूचना किसने दी थी। वह दोपहर 12-12:30 बजे घटना स्थल पर पहुँचे और पाया कि पुलिस घटना स्थल पर मौजूद थी। उन्होंने स्वीकार किया कि जिस स्थान पर उनके भाई की हत्या हुई थी, वहाँ से पुलिस स्टेशन पहुँचने के लिए 1-1/2 (डेढ़) घंटे का समय आवश्यक है। उन्हें अपने भाई इश्तियाक की हत्या की सूचना वीरमपुर में रात

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

लगभग 10-10:30 बजे मिली थी। जब वह घटना स्थल पर पहुँचे, तो रिपोर्ट पहले से ही जब्बार द्वारा लिखी गई थी और उनसे उस पर हस्ताक्षर कराए गए थे। वह नहीं जानते कि जब्बार को रिपोर्ट किसने लिखवाई क्योंकि उस समय वह काफी घबराए हुए थे। वह नहीं जानते कि रिपोर्ट में क्या लिखा था। वह गाँव में नहीं रहते हैं और किठौर में रहते हैं और वहाँ पढ़ते हैं। वह वीरमपुर में शादी में शामिल होने गए थे जहाँ से उन्हें बुलाया गया था। उन्होंने किसी भी साक्षी से बात नहीं की थी। मृतक के शव को उनके सामने सील किया गया था।

12. पी.डब्ल्यू.-2, खिलाफत ने कहा कि वह दोपहर लगभग 12:30 बजे अरबाज़ के साथ मंसूर अली के ट्यूबवेल पर बैठा था और खालिद (पी.डब्ल्यू.-1) तथा इश्तियाक (मृतक) उनसे 10 कदम की दूरी पर खड़े थे, जब अभियुक्त व्यक्ति आए थे। सरफराज़ और इखलाक के पास बंदूकें थीं और अन्य के पास देशी तमंचे थे। उन्होंने कहा कि चलो लताफत की हत्या का बदला लेते हैं और उन्होंने इश्तियाक पर गोली चलाई, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इश्तियाक का भाई खालिद (पी.डब्ल्यू.-1) सड़क के दूसरी तरफ खड़ा था। उन्होंने अपनी आँखों से घटना देखा था। वह एक घंटे तक घटना स्थल पर रहे और उसके बाद अपने घर चले गए।

13. अपनी जिरह में, उन्होंने बताया कि गाँव के रिश्ते के अनुसार इश्तियाक उनका भतीजा था। उन्होंने आगे बताया कि घटना के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा उनसे पूछताछ नहीं की गई थी। वह यह नहीं बता सकते कि अभियुक्त किस दिशा से आए और कौन आगे था और कौन पीछे था। उन सभी ने 4-5 कदम की दूरी से गोली चलाई थी। इश्तियाक उसी जगह मर गया ,जहाँ वह गिरा था। मृतक के गिरने के बाद, उन्होंने शोर मचाया और अभियुक्त ओझल हो गए। वह इश्तियाक के पास गए। वह न तो हिल रहा था और न ही बोल रहा था और वह समझ गए कि उसकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने न तो उसे छुआ और न ही उसे पलटा। वहाँ 20 अन्य लोग जमा हो गए थे, लेकिन वह किसी का नाम नहीं बता सकते है।

14. उन्होंने अपनी जिरह में आगे स्वीकार किया कि उनके ससुर बुंदा और उनके साले नामतः इस्लाम, होकाब, साबिर, सौरव और आसम उनके गाँव में रहते थे। उनके ससुर बुंदा पर गोलियां चलाई गई थीं और उस वाद में इखलाक (मृतक, अपीलार्थी संख्या 3) भी एक अभियुक्त था। उनके सालों के विरुद्ध भी वाद दर्ज थे। अब वे वापस अपने गाँव टोडी चले गए हैं। बुंदा ने इस वाद की पैरवी नहीं किया, सलमान और अन्य अभियुक्त एक ही परिवार के हैं, लेकिन वह उनके विरूद्ध बयान उनकी पुरानी शत्रुता के कारण नहीं बता सकते। उन्होंने आगे बताया कि इश्तियाक के पास

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

कोई जमीन नहीं थी। जमीन उसके पिता के नाम दर्ज थी और उसके तीन भाई थे नामतः हारून, खालिद और जाहिद, जो घटना के समय गाँव में एक ही घर में रहते थे। वह नहीं जानते कि इश्तियाक कितने मामलों में फँसा था और उसके भाई कितने मामलों में फँसे थे। वह घटना के दिन दोबारा घटना स्थल पर नहीं गए। पुलिस ने कभी उनसे पूछताछ नहीं किया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका एक बार आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत चालान किया गया था। उनका बेटा हसरत है, जिस पर एक वाद में विचारण चला और वह दोषमुक्त हो गया। उसके विरूद्ध दूसरा वाद दहेज का था। उनके बेटे के विरूद्ध चोरी का कोई वाद दर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी वाद में इश्तियाक (मृतक) के सह-अभियुक्त नहीं थे और न ही वह जानते हैं कि इश्तियाक कितनी बार जेल गया। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि घटना सुबह लगभग 10:00 बजे हुई थी और उन्होंने खालिद (पी.डब्ल्यू.-1) को वीरमपुर से बुलाया था। उन्होंने कहा कि खालिद घटना स्थल पर मौजूद था।

15. पी.डब्ल्यू.-3, डॉ. ए.पी. गुप्ता, शव-परीक्षण करने वाले डॉक्टर ने मृतक इश्तियाक के शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व चोटें पाईं:

(i). छाती और पेट की गुहा तक गहरा 4 सेमी x 4 सेमी का आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव, पेट के दाहिनी ओर छाती पर दाहिने निप्पल से 9 सेमी नीचे, घाव के किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए और आसपास के 12 सेमी x 10 सेमी क्षेत्र में टैटूइंग, घाव के अंदर रक्त मौजूद।

(ii). छाती की गुहा तक गहरा 3 सेमी x 3 सेमी का आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव, बाईं ओर बाएं निप्पल से 3 सेमी नीचे, किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए, गहरा रक्त मौजूद, आसपास के 12 सेमी x 10 सेमी क्षेत्र में टैटूइंग।

(iii). दाहिने ऊपरी और निचले छोर तथा कोहनी पर 2.5 सेमी x 2.5 सेमी x 3 सेमी गहरा आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव, किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए।

(iv). दाहिने कोहनी के जोड़ और दाहिनी रेडियस हड्डी तक गहरा 6 सेमी x 4 सेमी का आग्नेयास्त्र का निकास घाव, चोट संख्या 3 और 4 के बीच निरंतरता स्थापित।

(v). 1 सेमी x 1 सेमी का आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव, मांसपेशी तक गहरा, किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए, गर्दन के दाहिनी ओर और गर्दन की जड़ के आधार के नीचे टैटूइंग।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Translated Version. Not for Legal Use.

(vi). गर्दन की बाईं ओर 1.5 सेमी x 1.5 सेमी गुहा तक गहरा निकास घाव।

(vii). गर्दन और कंधे के जोड़ पर ऊपर की ओर जाता हुआ निकास घाव, बाईं ऊपरी भुजा के बाहरी हिस्से पर।

(viii). बाएं कूल्हे पर नितंब तक 1 सेमी x 1 सेमी का आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव, मांसपेशी तक गहरा, आसपास टैटूइंग मौजूद।

16. डॉक्टर ने मृतक के पूरे शरीर पर रिगर मोर्टिस मौजूद पाया। उसका पेट खाली था, जिससे सिद्ध हुआ कि उसने पिछले तीन घंटों से कुछ भी नहीं खाया था। उन्होंने राय दिया कि मृतक की मृत्यु की अधिकतम अवधि 36 घंटे तक हो सकती है।

17. पी.डब्ल्यू.-4 ने सिद्ध किया कि वह इस वाद के विवेचना अधिकारी थे। उन्होंने अपनी उपस्थिति में वाद दर्ज कराया और विवेचना शुरू किया। उन्होंने पी.डब्ल्यू.-1 का बयान दर्ज किया; पंचायतनामा कराया; नक्शा-नजरी बनाया और चक्षुदर्शी साक्षी इखलाक और मंसूर अली के बयान दर्ज किए। उन्होंने 19.06.1993 को जिला मेरठ में सभी अभियुक्तों के बयान दर्ज किए और अभियुक्त फारुख का पुलिस रिमांड लेने के बाद, 25.06.1993 को आम के बाग से .315 बोर का देशी तमंचा बरामद किया। उसी दिन ममनून, महबूब और मारूफ ने भी उसी बाग से .315 बोर के देशी तमंचे बरामद कराए। उन्होंने घटना स्थल से मिट्टी के नमूने और 12 बोर के दो खाली कारतूस और .315 के दो खाली कारतूस एकत्र किए और उनकी फर्द बरामदगी तैयार किया। उन्होंने फर्द बरामदगी पर अपने हस्ताक्षर और लिखावट को सिद्ध किया। उन्होंने आगे बताया कि अभियुक्त जराफत, इखलाक के पास लाइसेंसी बंदूकें थीं, जिन्हें उन्होंने हापुड़ के शस्त्र डीलर के पास जमा कर दिया था। उन्हें 10.6.1993 को इस वाद की विवेचना सौंपी गई थी और 28.6.1993 को उन्होंने उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।

18. अपनी जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि सूचनादाता ने खुद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखी और अपने हस्ताक्षर किए। उन्होंने यह पता लगाने के उद्देश्य से रिपोर्ट की तुलना नहीं की कि उसे किसने लिखा है। उन्हें पुलिस स्टेशन पर 14:15 बजे घटना की सूचना मिली और वह घटना स्थल पर गए, लेकिन उन्होंने केस डायरी में वह समय दर्ज नहीं किया है, जब उन्होंने विवेचना शुरू की थी। वह यह नहीं बता सकते कि उन्होंने नक्शा-नजरी कब तैयार किया और सादी तथा खून से सनी मिट्टी कब एकत्र की और अन्य दस्तावेज़ कब तैयार किए। उन्होंने इस बात से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

इनकार किया कि पंचायतनामा उनकी अनुपस्थिति में तैयार किया गया था और उन्होंने बाद में उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने पंचायतनामा देखा नहीं था, बल्कि अपनी केस डायरी में रिपोर्ट की नकल की थी। यह उनके निर्देश पर तैयार किया गया था। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने पंचायतनामा रिपोर्ट (प्रदर्श ए-3) पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि इसे उनके निर्देश पर उप-निरीक्षक राम प्रकाश ने तैयार किया था। उन्होंने स्वीकार किया कि पंचायतनामा रिपोर्ट में सूचना की तिथि का उल्लेख था, लेकिन समय का नहीं उल्लेख नहीं था। धारा 302 भा.द.सं. नीचे लिखी है और धारा 147, 148, 149 भा.द.सं. ऊपर लिखी हैं, क्योंकि उस समय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। उन्होंने स्वीकार किया कि नक्शा-नजरी में उन्होंने वह पेड़ नहीं दिखाया है, जिसके नीचे साक्षी बैठे थे। वह नहीं जानते कि मंसूर अली के ट्यूबवेल पर कोई पेड़ था या नहीं। वह यह नहीं बता सकते कि मृतक के कपड़े शव-परीक्षण डॉक्टर द्वारा भेजे गए थे या नहीं। वह न्यायालय को यह सूचित करने में विफल रहे कि मृतक के कपड़ों पर गोली चलने के कोई निशान थे या नहीं। उन्होंने डीलर से अभियुक्त जराफत और खालिद की लाइसेंसी बंदूकों के बारे में पूछताछ नहीं किया। उन्होंने मौके से बरामद खाली कारतूसों से हथियारों के मिलान के संबंध में विशेषज्ञ से कोई एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त नहीं की क्योंकि उनका स्थानांतरण दूसरे पुलिस स्टेशन में हो गया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने 10.06.1993 को खिलाफत का बयान दर्ज किया था।

19. पी.डब्ल्यू.-5 एक औपचारिक साक्षी है और उसकी गवाही बहुत प्रासंगिक नहीं है।

20. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि फर्द बरामदगी (प्रदर्श क-10) दर्शाता है कि 10.06.1993 को जब्बार और आसिफ अली की उपस्थिति में घटना स्थल से 12 बोर के 2 खाली कारतूस और .315 बोर के 2 खाली कारतूस बरामद किए गए थे; फर्द बरामदगी (प्रदर्श क-12) दर्शाता है कि अभियुक्त ममनून की निशानदेही पर जब्बार और इस्लाम की उपस्थिति में 25.06.1993 को रात 12:45 बजे (मध्यरात्रि) एक खुली जगह से .315 बोर का देशी तमंचा बरामद किया गया था; फर्द बरामदगी (प्रदर्श क-13) दर्शाता है कि अभियुक्त महबूब की निशानदेही पर जब्बार और इस्लाम की उपस्थिति में 25.06.1993 को रात 01:10 बजे (मध्यरात्रि) एक खुली जगह से .315 बोर का देशी तमंचा बरामद किया गया था; फर्द बरामदगी (प्रदर्श क-14) दर्शाता है कि अभियुक्त मारूफ की निशानदेही पर जब्बार और इस्लाम की उपस्थिति में 25.06.1993 को रात 02:45 बजे (मध्यरात्रि) एक खुली जगह से .315 बोर का देशी तमंचा बरामद किया गया था; फर्द बरामदगी (प्रदर्श क-15) दर्शाता है कि अभियुक्त फारुख की निशानदेही पर जब्बार और इस्लाम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Translated Version. Not for Legal Use.

की उपस्थिति में 25.06.1993 को रात 12:15 बजे (मध्यरात्रि) एक खुली जगह से .315 बोर का देशी तमंचा बरामद किया गया था; अभियोजन जब्बार और इस्लाम का परीक्षण करने में विफल रहा है, जो हथियारों की बरामदगी के मुख्य साक्षी हैं; अभियोजन कारतूस या बरामद देशी तमंचों की वैज्ञानिक जाँच कराने में विफल रहा है; एफ.एस.एल. रिपोर्ट की अनुपस्थिति में और बरामदगी के साक्षीगण का परीक्षण न होने के कारण, इस तथ्य के साथ कि परीक्षित चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यू.-1 ने घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति से इनकार किया है और पी.डब्ल्यू.-2 एक हितबद्ध साक्षी है, अभियुक्तों को कथित हथियारों से नहीं जोड़ा जा सकता है और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के **सुखवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1995) 3 एससीसी 367)-प्रस्तर 21** और **महावीर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य ((2016) 10 एससीसी 220)-प्रस्तर 23-27** के निर्णयों पर भरोसा किया गया है।

21. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श क-2) आग्नेयास्त्र के पाँच प्रवेश घाव और तीन निकास घाव दर्शाती है, लेकिन ऐसी कोई चोट नहीं है, जो 12 बोर की बंदूक से लग सके; पोस्टमार्टम रिपोर्ट संकेत देती है कि मृत्यु के समय मृतक के पेट में कोई भोजन मौजूद नहीं था; यह परिस्थिति इस बात को अत्यधिक असंभव बनाती है कि घटना जून के माह में दोपहर 12:30 बजे हुई थी और इसके बजाय यह संकेत देती है कि घटना सुबह के घंटों के दौरान हुई थी; पोस्टमार्टम डॉ. ए.पी. गुप्ता (पी.डब्ल्यू.3) द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपनी जिरह में कहा है कि वह मृतक के कपड़ों में छेद की उपस्थिति को अंकित करने में विफल रहे हैं। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के **राम नारायण सिंह बनाम पंजाब राज्य ((1975) 4 एससीसी 497)-प्रस्तर 14** के निर्णय पर भरोसा किया है।

22. उनका तर्क यह भी है कि सूचनादाता और चक्षुदर्शी साक्षी खालिद (पी.डब्ल्यू.1) का बयान दर्शाता है कि वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, और जब वह पहुँचा, तो रिपोर्ट पहले से ही लिखी हुई थी, और उसने केवल रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे; कथित सूचनादाता और चक्षुदर्शी साक्षी खालिद (पी.डब्ल्यू.-1) जिरह के दौरान पक्षद्रोही हो गया; हालाँकि, अभियोजन ने न तो उसे पक्षद्रोही घोषित किया और न ही आगे उससे जिरह किया।

23. इस संबंध में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया गया है;

i. सत पाल बनाम दिल्ली प्रशासन ((1976) 1 एससीसी 727) - प्रस्तर 30 से 57।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

ii. रमेश हरिजन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ((2012) 5 एससीसी 777) - प्रस्तर 23 से 32।

24. चक्षुदर्शी साक्षी खिलाफत (पी.डब्ल्यू.-2) एक हितबद्ध साक्षी है और अभियुक्तों के प्रति शत्रुता रखता है, क्योंकि वह पहले एक पुराने प्रकरण में शामिल था, जिसमें उसके ससुर को गोली मारी गई थी, जिसमें अपीलार्थी संख्या 3 (इखलाक) को उसके साले के साथ फँसाया गया था।

25. चक्षुदर्शी साक्षी खिलाफत (पी.डब्ल्यू.-2) की गवाही खामियों से भरी है और न तो अन्य अभियोजन साक्षीगण के बयानों की पुष्टि करती है और न ही प्रश्नगत घटना की पुष्टि करती है। उसका बयान संकेत देता है कि, पूरी संभावना में, वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था और केवल सुनी-सुनाई जानकारी दोहरा रहा है। इसके अलावा, उसका बयान कभी भी धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज नहीं किया गया था, और उसने पहली बार सीधे विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष बयान दिया है।

26 चक्षुदर्शी साक्षी खिलाफत (पी.डब्ल्यू.-2) एक अविश्वसनीय साक्षी भी है, क्योंकि उसने कहा है कि पी.डब्ल्यू.-1 खालिद घटना स्थल पर मौजूद था, जबकि पी.डब्ल्यू.-1 ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति से इनकार किया है।

27. विवेचना अधिकारी ने अपनी जिरह में कहा है कि उन्होंने अपनी केस डायरी में विवेचना का समय दर्ज नहीं किया, न ही मिट्टी की बरामदगी का समय और पंचायतनामा रिपोर्ट पर भी कोई समय नहीं बताया गया है, और आई.ओ. के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं; पंचायतनामा में धाराओं की ओवरराइटिंग है; प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लाइसेंसी बंदूकों से गोलीबारी के संबंध में था, और विवेचना के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि उनकी लाइसेंसी बंदूकें डीलर के पास रखी हैं, आई.ओ. ने इस तथ्य की विवेचना नहीं किया; कोई बैलिस्टिक रिपोर्ट एकत्र नहीं की गई; पी.डब्ल्यू.2, जो चक्षुदर्शी साक्षी होने का दावा करता है, उसका बयान भी विवेचना अधिकारी द्वारा धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज नहीं किया गया था।

28. विद्वान ए.जी.ए. और सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन ने इस वाद में उचित संदेह से परे अपना प्रकरण सिद्ध किया है। साक्षीगण की ओर से छोटी-मोटी चूक और विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी द्वारा की गई गलतियाँ, ऐसी प्रकृति की नहीं हैं कि अभियोजन के प्रकरण को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया है कि यह दिनदहाड़े हुई हत्या का वाद है और अपीलार्थी नामजद अभियुक्त हैं, जो इस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

न्यायालय द्वारा किसी भी उदारता के पात्र नहीं हैं। अपील गुण-दोष से विहीन है और इसे खारिज किया जा सकता है।

29. प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद, हम पाते हैं कि इस वाद में मृतक को अलग-अलग हथियारों से आग्नेयास्त्र की चोटें पहुँचाई गई थीं और छह व्यक्तियों को बिना किसी विशिष्ट आग्नेयास्त्र द्वारा कारित विशिष्ट चोट आवंटित कर फँसाया गया था। इस वाद में बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि विवेचना अधिकारी द्वारा बरामद आग्नेयास्त्र और कारतूसों का मिलान किया जाना आवश्यक था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

30. अभियुक्तों की निशानदेही पर खुली जगह से बिना अभियुक्त का कोई पूर्व प्रकटीकरण कथन दर्ज कर हथियारों की केवल बरामदगी अभियोजन के प्रकरण को और अधिक संदिग्ध बनाती है। इसके अलावा बरामदगी के साक्षीगण नामतः जब्बार और इस्लाम को इसे सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में पेश नहीं किया गया।

31. विवादित घटना 10.06.1993 को दोपहर 12:30 बजे हुई थी, लेकिन मृतक का पेट खाली था जो अभियोजन पक्ष के वाद पर संदेह पैदा करता है। बचाव पक्ष का यह मामला कि घटना का समय सुबह जल्दी हो सकता है, विश्वसनीय लगता है। अभियोजन पक्ष के साक्षीगण का यह पक्ष कि चूंकि मृतक शादी में शामिल होने जा रहा था, इसलिए उसने घटना के दिन और अपनी मृत्यु से पहले कुछ भी नहीं खाया था, सामान्य मानवीय आचरण को देखते हुए विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पी.डब्ल्यू.-1 ने बताया है कि उसे घटना की सूचना वीरमपुर में सुबह 10-10:30 बजे मिली और फिर वह दोपहर 12-12:30 बजे घटना स्थल पर आया। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक की मृत्यु सुबह 10-10:30 बजे से पहले हुई थी और इसीलिए उसका पेट खाली पाया गया था। चिकित्सा साक्ष्य इस संबंध में अभियोजन के प्रकरण का खंडन करते हैं और अभियोजन के प्रकरण में फिर से एक गंभीर कमी है।

32. सबसे महत्वपूर्ण विरोधाभास पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 के बयानों के बीच पाया जाता है। दोनों ने घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होने का दावा किया और उपरोक्त दोनों साक्षीगण के बयान पुलिस के विवेचना अधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किए गए थे। वे सीधे न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित हुए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

33. धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता पुलिस द्वारा साक्षीगण को परीक्षित करने का प्रावधान करती है। उप-धारा (1) प्रावधान करती है कि इस अध्याय के अंतर्गत विवेचना करने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति का मौखिक परीक्षण कर सकता है, जिसके वाद के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होने की संभावना है और ऐसा व्यक्ति उप-धारा (2) के अंतर्गत ऐसे वाद से संबंधित सभी प्रश्नों के सही उत्तर देने के लिए बाध्य होगा। उप-धारा (3) के अंतर्गत पुलिस अधिकारी इस धारा के अंतर्गत परीक्षण के दौरान उसे दिए गए, किसी भी बयान को लिपिबद्ध कर सकता है; और यदि वह ऐसा करता है, तो वह उसका एक अलग और सही रिकॉर्ड बनाएगा। धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता नीचे उद्धृत की गई है:

*"**161- पुलिस द्वारा साक्षीगण का परीक्षण:-** (1) इस अध्याय के अधीन विवेचना करने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी, या ऐसे पद से नीचे का न हो, कोई भी पुलिस अधिकारी, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे, ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करते हुए, उस व्यक्ति की मौखिक रूप से परीक्षण कर सकता है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह वाद के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है।*

(2) ऐसा व्यक्ति ऐसे अधिकारी द्वारा उससे पूछे गए वाद से संबंधित सभी सवालों के सही जवाब देने के लिए बाध्य होगा, उन सवालों को छोड़कर जिनके जवाब उसे किसी आपराधिक आरोप या दंड या जब्ती के लिए उजागर करने की प्रवृत्ति रखते हैं।

(3) पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षण के दौरान उसे दिए गए किसी भी बयान को लेखबद्ध कर सकता है; और यदि वह ऐसा करता है, तो वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के बयान का एक अलग और सही रिकॉर्ड बनाएगा जिसका बयान वह दर्ज करता है। बशर्ते कि इस उप-धारा के अधीन दिया गया बयान ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी दर्ज किया जा सकता है"

34- धारा 162 दंड प्रक्रिया संहिता यह प्रावधान करती है कि इस अध्याय के अधीन किसी विवेचना के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई भी बयान, यदि लेखबद्ध किया जाता है, तो उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा; और न ही ऐसा कोई बयान या उसका कोई रिकॉर्ड, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या अन्यथा, या ऐसे रिकॉर्ड के बयान का कोई भाग, इसमें इसके पश्चात प्रदान किए गए को छोड़कर, किसी भी प्रयोजन के लिए, किसी भी ऐसे अपराध के संबंध में किसी भी जांच या विचारण में उपयोग किया जाएगा, जो उस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

समय विवेचना के अधीन था, जब ऐसा बयान दिया गया था। धारा 162 की उप-धारा (1) के साथ संलग्न परंतुक यह प्रावधान करता है कि जब किसी साक्षी को ऐसी जांच या विचारण में अभियोजन पक्ष के लिए बुलाया जाता है, जिसका बयान पूर्वोक्त रूप से लेखबद्ध किया गया है, तो उसके बयान का कोई भी भाग, यदि विधिवत सिद्ध हो जाता है, तो अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुमति से अभियोजन पक्ष द्वारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 145 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से ऐसे साक्षी का खंडन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, और जब ऐसे बयान के किसी भी भाग का इस प्रकार उपयोग किया जाता है, तो उसके किसी भी भाग का उपयोग ऐसे साक्षी के पुनः परीक्षण में भी किया जा सकता है, लेकिन केवल उसकी जिरह में संदर्भित किसी भी मामले को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। धारा 162 दंड प्रक्रिया संहिता नीचे उद्धृत की गई है:-

"162- पुलिस को दिए गए बयानों पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे : साक्ष्य में बयानों का उपयोग।

(1) इस अध्याय के अधीन किसी विवेचना के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई भी बयान, यदि लेखबद्ध किया जाता है, तो उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा; और न ही ऐसा कोई बयान या उसका कोई रिकॉर्ड, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या अन्यथा, या ऐसे रिकॉर्ड के बयान का कोई भाग, इसमें इसके पश्चात प्रदान किए गए को छोड़कर, किसी भी प्रयोजन के लिए, किसी भी ऐसे अपराध के संबंध में किसी भी जांच या विचारण में उपयोग किया जाएगा, जो उस समय विवेचना के अधीन था, जब ऐसा बयान दिया गया था, बशर्ते कि जब किसी गवाह को ऐसी जांच या विचारण में अभियोजन पक्ष के लिए बुलाया जाता है, जिसका बयान पूर्वोक्त रूप से लेखबद्ध किया गया है, तो उसके बयान का कोई भी भाग, यदि विधिवत सिद्ध हो जाता है, तो अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुमति से अभियोजन पक्ष द्वारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1 वर्ष 1872) की धारा 145 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से ऐसे साक्षी का खंडन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है; और जब ऐसे बयान के किसी भी भाग का इस प्रकार उपयोग किया जाता है, तो उसके किसी भी भाग का उपयोग ऐसे गवाह की पुनः परीक्षा में भी किया जा सकता है, लेकिन केवल उसकी जिरह में संदर्भित किसी भी मामले को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है।

(2) इस धारा की किसी भी बात को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 32 के खंड (1) के प्रावधानों के भीतर आने वाले किसी भी बयान पर लागू होने वाला नहीं माना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

जाएगा, या उस अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा। स्पष्टीकरण। - उप-धारा (1) में संदर्भित बयान में किसी तथ्य या परिस्थितियों को बताने में कोई चूक खंडन के समान हो सकता है, यदि वह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण और अन्यथा प्रासंगिक प्रतीत होती है जिसमें ऐसी चूक होती है और क्या कोई चूक विशेष संदर्भ में खंडन के समान है, यह तथ्य का प्रश्न होगा।"

35- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 145 लिखित में पिछले बयानों के संबंध में एक साक्षी की जिरह का प्रावधान करती है। यह प्रावधान करती है कि एक साक्षी से उसके द्वारा लिखित रूप में दिए गए या लेखबद्ध किए गए पिछले बयानों के बारे में, और प्रश्नगत मामलों से प्रासंगिक होने पर, ऐसी लिखत को उसे दिखाए बिना, या सिद्ध किए बिना जिरह की जा सकती है; लेकिन, यदि लिखत द्वारा उसका खंडन करने का आशय है, तो लिखत को सिद्ध किए जा सकने से पहले, उसका ध्यान उसके उन भागों की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए जिनका उपयोग उसका खंडन करने के प्रयोजन के लिए किया जाना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 145 नीचे उद्धृत की गई है:-

"145- लिखित में पिछले बयान के बारे में जिरह:-

एक साक्षी से उसके द्वारा लिखित रूप में दिए गए या लेखबद्ध किए गए पिछले बयानों के बारे में, और प्रश्नगत मामलों से प्रासंगिक होने पर, ऐसी लिखत को उसे दिखाए बिना, या सिद्ध किए बिना जिरह की जा सकती है; लेकिन, यदि लिखत द्वारा उसका खंडन करने का आशय है, तो लिखत को सिद्ध किए जा सकने से पहले, उसका ध्यान उसके उन भागों की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए, जिनका उपयोग उसका खंडन करने के प्रयोजन के लिए किया जाना है।"

36- उपरोक्त के आलोक में, किसी भी अपराध का विवेचना करने वाला पुलिस अधिकारी वाद के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित माने जाने वाले किसी भी व्यक्ति की मौखिक रूप से परीक्षण कर सकता है और उसके द्वारा दिए गए किसी भी बयान को लेखबद्ध कर सकता है। उक्त बयान का उपयोग विवेचना के अधीन किसी भी अपराध के संबंध में किसी भी जांच या विचारण में नहीं किया जा सकता है, लेकिन उक्त बयान का उपयोग साक्षी द्वारा अपनी जिरह में संदर्भित किसी भी मामले को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए उक्त गवाह का खंडन करने के लिए किया जा सकता है। अभियुक्त जिरह में उक्त साक्षी का खंडन धारा 145 के अधीन प्रदान किए गए तरीके

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

से कर सकता है, जिसमें उसकी लिखत को भी सिद्ध कराया जा सकता है। चूँकि धारा 162(1) के परंतुक में अभियुक्त को अधिकार दिया गया है, इसलिए, धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन दर्ज ऐसे साक्षी का बयान जिरह के समय उसके बचाव के लिए महत्वपूर्ण होगा। विधि में यह स्थापित है कि विचारण के दौरान प्रत्येक अभियुक्त को अपनी बेगुनाही सिद्ध करने के लिए बचाव का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाएगा, इसलिए, विधि अभियुक्त को सभी प्रासंगिक सामग्री प्रदान करने का भी प्रावधान करता है। धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन दर्ज बयानों को धारा 207(iii) दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाना भी आवश्यक है। धारा 207(iii) दंड प्रक्रिया संहिता नीचे उद्धृत की गई है:-

" 207- अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ों की प्रति की आपूर्ति:-

किसी भी वाद में जहाँ पुलिस रिपोर्ट पर कार्यवाही संस्थित की गई है, मजिस्ट्रेट बिना किसी विलंब के अभियुक्त को, नि:शुल्क, निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रति प्रस्तुत करेगा;

(i)..........

(ii).........

(iii) उन सभी व्यक्तियों के धारा 161 की उप-धारा (3) के अधीन दर्ज किए गए बयान जिनका अभियोजन पक्ष अपने साक्षीगण के रूप में परीक्षण करने का प्रस्ताव करता है, उनमें से उस भाग को छोड़कर, जिसके संबंध में धारा 173 की उप-धारा (6) के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे निष्कासन के लिए अनुरोध किया गया है;

(iv).........

(v)...........

बशर्ते कि मजिस्ट्रेट, खंड (iii) में संदर्भित बयान के किसी ऐसे भाग का परिशीलन करने और अनुरोध के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करने के बाद, यह निर्देश दे सकता है कि बयान के उस भाग की या उसके ऐसे हिस्से की एक प्रति ,जो मजिस्ट्रेट उचित समझे, अभियुक्त को प्रस्तुत की जाएगी;

बशर्ते यह भी कि यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि खंड (v) में संदर्भित कोई भी दस्तावेज़ विशाल है, तो वह अभियुक्त को उसकी एक प्रति प्रस्तुत करने के बजाय, यह निर्देश देगा कि उसे केवल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Translated Version. Not for Legal Use.

व्यक्तिगत रूप से या न्यायालय में अभिवक्ता के माध्यम से इसका निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी।"

37- इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने **गोपाल कृष्ण बनाम राज्य एआईआर 1964 इला 481** के वाद में यह टिप्पणी किया है कि यह स्पष्ट है कि यद्यपि पुलिस धारा 161 के अधीन एक बाध्यता के मामले के रूप में साक्षीगण के बयान का रिकॉर्ड बनाने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन ऐसा करना उनका कर्तव्य है, जब साक्षी अभियोजन की कहानी को उजागर करने के लिए एक महत्वपूर्ण साक्षी है। यह भी स्पष्ट है कि धारा 161(3) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में उनकी ओर से विफलता, यद्यपि विचारण में साक्षी के बाद के बयान को अग्राहय नहीं बनाती है, लेकिन यह उस साक्षी के साक्ष्य के मूल्य को बहुत कम कर देती है। इस प्रकार न्यायालय ने राय दी कि ऐसे साक्षी का बयान अपना बहुत सारा वज़न खो देता है और विचारण में प्रस्तुत किए गए साक्षीगण द्वारा दिया गया साक्ष्य के मूल्य का विश्लेषण किया जाना चाहिए। प्रासंगिक प्रस्तर 19 से 23 नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

"19- धारा 161(3) इस प्रकार है:

"पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षण के अनुक्रम में उसे दिए गए किसी भी बयान को लेखबद्ध कर सकता है"

20- धारा 164(1) भी यह प्रावधान करती है कि "कोई भी प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट .... इस अध्याय के अधीन किसी विवेचना के अनुक्रम में उसे दिया गया कोई भी बयान या संस्वीकृति दर्ज कर सकता है।

नज़ीर अहमद बनाम किंग एम्परर, एआईआर 1936 पीसी 253 (2) *के वाद में धारा 164 में प्रयुक्त 'कर सकता है' शब्द पर टिप्पणी की गई थी और माननीय न्यायमूर्ति ने निम्नानुसार टिप्पणी करना उचित समझा:*

"इसमें शायद ही कोई संदेह हो सकता है कि कोई मजिस्ट्रेट उसे की गई किसी भी संस्वीकृति को दर्ज करने के लिए बाध्य नहीं होगा यदि, उदाहरण के लिए, वह स्वयं पर आरोप लगाने वाले किसी पागल व्यक्ति की हो या किन्हीं अन्य कारणों से मजिस्ट्रेट इसे अविश्वसनीय या न्याय के प्रयोजनों के लिए बेकार समझे। क्या कोई मजिस्ट्रेट कोई संस्वीकृति दर्ज करता है, यह कर्तव्य और विवेक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Translated Version. Not for Legal Use.

का मामला है और बाध्यता का नहीं।" ***<u>पुरुषोत्तम जेठानंद बनाम कच्छ राज्य, एआईआर 1954 एससी 700</u>*** *के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया था:*

"इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि विवेचना के दौरान साक्षीगण द्वारा दिए गए बयानों की प्रतियां प्राप्त करने का जो अधिकार अभियुक्त को मिला है, वह एक बहुत ही मूल्यवान अधिकार है और इसे प्रदान करने से थोक रूप से इनकार करना एक गंभीर अनियमितता होगी, जो संपूर्ण विचारण को दूषित कर देगी, जैसा कि ***<u>कोट्टाया बनाम एम्परर, एआईआर 1947 पीसी 67 में प्रिवी काउंसिल</u>*** *द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था।"*

21- ***<u>तिलकेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, (एस) एआईआर 1956 एससी 238</u>*** *के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161(3) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफलता साक्षीगण के साक्ष्य से जुड़े जाने वाले वज़न को प्रभावित कर सकती है, यह इसे अग्राह्य नहीं बनाती है।*

22- *इन प्राधिकारियों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि यद्यपि पुलिस धारा 161 के अधीन एक बाध्यता के रूप में साक्षीगण के बयान का रिकॉर्ड बनाने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन ऐसा करना उनका कर्तव्य है, जब साक्षी अभियोजन की कहानी को उजागर करने के लिए एक महत्वपूर्ण साक्षी है। यह भी स्पष्ट है कि धारा 161(3) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में उनकी ओर से विफलता, यद्यपि विचारण में गवाह के बाद के बयान को अग्राह्य नहीं बनाती है, लेकिन यह उस साक्षी के साक्ष्य के मूल्य को बहुत कम कर देती है। इसलिए, हमारी राय है कि विचारण में पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 के बयान, यद्यपि साक्ष्य में ग्राह्य हैं, इस तथ्य के कारण अपना बहुत सारा वज़न खो चुके हैं कि उनका बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन दर्ज नहीं किया गया था।*

23- *वाद में शामिल विधिक प्रश्न की उपरोक्त चर्चा के प्रकाश में, विचारण में प्रस्तुत किए गए साक्षीगण द्वारा दी गई गवाही के मूल्य का विश्लेषण किया जाना चाहिए।"*

38- इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने **शंकर लाल और अन्य बनाम राज्य एआईआर 1954 इला 779** के वाद में अभिनिर्धारित किया है कि उन साक्षीगण के बयानों पर किसी अभियुक्त को दोषसिद्ध करना सुरक्षित नहीं है, जिनसे प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से जिरह नहीं की गई है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

क्योंकि अपीलार्थियों को विधि द्वारा उन पर प्रदत्त एक मूल्यवान अधिकार से वंचित किया गया था।

39- जबकि पी.डब्ल्यू.-2 ने कहा कि पी.डब्ल्यू.-1 घटना स्थल पर उपस्थित था, पी.डब्ल्यू.-1 ने अपनी जिरह में इससे इनकार किया और कहा कि वह वीरमपुर में एक शादी में शामिल हो रहा था, जब उसे घटना की तिथि को सुबह 10-10:30 बजे घटना के बारे में सूचना मिली थी। उसके बाद, वह आया और उसने उस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किए जो एफ.आई.आर. दर्ज करने के प्रयोजन के लिए जब्बार द्वारा पहले ही लिखा गया था। उसने एफ.आई.आर. की अंतर्वस्तु को भी सिद्ध नहीं किया और कहा कि उसे नहीं पता कि रिपोर्ट में क्या लिखा गया था। उसने आगे कहा कि वह हिंदी भाषा में बहुत अच्छी तरह से पारंगत नहीं है और केवल अपना नाम लिख सकता है और केवल थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ और लिख सकता है। पी.डब्ल्यू.-1 के बयान की तुलना में पी.डब्ल्यू.-2 का बयान विचारण न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू.-1 द्वारा अपनी जिरह में कही गई बातों के साथ पूर्ण विरोधाभास में प्रतीत होता है।

40- पी.डब्ल्यू.-2 ने कहा कि पी.डब्ल्यू.-1 घटना स्थल पर उपस्थित था और उसने अपनी आँखों से घटना देखा था। पी.डब्ल्यू.-2 की अभियुक्तों के साथ शत्रुता थी, क्योंकि उसके ससुर, बुंदा पर इस वाद के अभियुक्तों में से एक इखलाक और उसके अन्य साथियों द्वारा गोली चलाने का मामला था। इसलिए, पी.डब्ल्यू.-2 के हितबद्ध साक्षी होने से इनकार नहीं किया जा सकता। साक्षीगण के बयानों में मामूली विरोधाभासों और विसंगतियों को निश्चित रूप से नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन इस वाद में पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 की गवाहियों में भारी विरोधाभास हैं, जो अभियोजन के प्रकरण की सत्यता की जड़ तक जाते हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

41- हम पाते हैं कि पी.डब्ल्यू.-1 ने अपनी जिरह में अभियोजन के प्रकरण का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया था। बल्कि उसने अभियोजन के प्रकरण को पूर्णतः नकार दिया जबकि उसने स्वयं को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होने का दावा किया था और अपनी मुख्य परीक्षा में, उसने विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन के प्रकरण को नकार दिया। इसलिए घटना का एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यू.-2 बचा था, जिसकी गवाही पी.डब्ल्यू.-1 की गवाही के साथ विरोधाभास में है और यह पाया गया कि उसकी सह-अभियुक्त, इखलाक द्वारा उसके ससुर, बुंदा के विरूद्ध की गई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

पिछली घटना के अभियुक्तों में से एक के साथ शत्रुता थी। इसलिए, पी.डब्ल्यू.-1 की जिरह में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो इस वाद में अभियोजन के प्रकरण की पुष्टि करता हो।

42- जबकि पी.डब्ल्यू.-1 पूर्णतः अविश्वसनीय साक्षी है। पी.डब्ल्यू.-2 ने एफ.आई.आर. के अनुरूप अभियोजन के प्रकरण को सिद्ध किया, लेकिन उसे पूर्णतः विश्वसनीय साक्षी नहीं कहा जा सकता। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह एक हितबद्ध साक्षी है, जिसकी अभियुक्त पक्ष के साथ शत्रुता है, इसलिए, उसकी गवाही को स्वीकार करने के लिए उसकी गवाही की पुष्टि की आवश्यकता थी, जो हमें वर्तमान वाद में नहीं मिलती है। पी.डब्ल्यू.-1 की गवाही, पी.डब्ल्यू.-2 की गवाही के साथ पूर्णतः युद्धरत है, इसलिए हम शेष अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और दंडादेश को बरकरार रखने के लिए केवल पी.डब्ल्यू.-2 की गवाही पर भरोसा करना असुरक्षित पाते हैं।

43- इस बात की पूरी संभावना है कि पी.डब्ल्यू.-2 अपने ससुर और सालों की उसके साथ शत्रुता के कारण सह-अभियुक्त, इखलाक और उसके साथियों से बदला लेने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ हो।

44- हमें यह दोहराना चाहिए कि जहाँ अभियोजन साक्षी/साक्षीगण का बयान विवेचना अधिकारी द्वारा धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन दर्ज नहीं किया जाता है, और वे सीधे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हैं, वहाँ बचाव पक्ष को पुलिस के विवेचना अधिकारी के समक्ष दिए गए, उनके पिछले बयानों के संबंध में साक्षीगण से जिरह करने के अवसर से वंचित कर दिया जाता है। इसलिए, ऐसे साक्षीगण की गवाही को सावधानी के साथ निपटाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी गवाही बचाव पक्ष के उनके पहले के बयानों से जिरह करने/सामना कराने के अधिकार को छीन लेती है, जो आपराधिक विचारण में साक्षीगण से सत्यता बाहर लाने के लिए आवश्यक है।

45- इस वाद में, धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज अभियुक्तों के बयान में, उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता से इनकार किया और शत्रुता के कारण झूठा फँसाए जाने का भी अभिकथन किया है। **प्रमिला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2021) 12 एससीसी 550** के वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियुक्त के परीक्षण में, उचित संदेह से परे प्रमाण के मानक की आवश्यकता लागू नहीं होता है। आरोप सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। अभियुक्त को केवल अभियोजन के प्रकरण के संबंध

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

में संदेह पैदा करने की आवश्यकता होती है और फिर अभियोजन पक्ष को अपना प्रकरण उचित संदेह से परे स्थापित करना होता है। धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपने बयान में अन्यत्र उपस्थिति की दलील स्थापित करने में अभियुक्त की विफलता, अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त का बयान कोई साक्ष्य नहीं है। यह न तो शपथ पर होता है और न ही अभियोजन पक्ष को अभियुक्त से जिरह करने का अवसर मिलता है। इसलिए, अभियोजन पक्ष का अपना प्रकरण सिद्ध करने का भार कम नहीं होता है। वर्तमान वाद में हम पाते हैं कि पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 के बयान विश्वसनीय नहीं हैं और विचारण न्यायालय के समक्ष तथ्य का कोई अन्य साक्षी पेश नहीं किया गया था, जिसके बयान पर पुष्टि के प्रयोजन के लिए भरोसा किया जा सकता था।

46- इस वाद के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों के अधीन, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष शेष अपीलार्थियों के विरूद्ध उचित संदेह से परे अपना प्रकरण सिद्ध करने में विफल रहा है।

47- विदा लेने से पहले हमें यह अभिलेख पर लाना चाहिए कि हम इस विधि से अनभिज्ञ नहीं हैं कि भले ही साक्षी पक्षद्रोही हो जाए, अभियोजन के प्रकरण को सिद्ध करने वाली उसकी गवाही के भाग को स्वीकार किया जाना चाहिए। इस वाद में पी.डब्ल्यू.-1 की गवाही का भाग यद्यपि अभियोजन के प्रकरण का समर्थन करता है, लेकिन इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विवेचना अधिकारी द्वारा उससे कभी पूछताछ नहीं की गई और उसने बाद में घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति से इनकार कर दिया है और एफ.आई.आर. की अंतर्वस्तु को भी सिद्ध नहीं किया है, हम शेष अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और दंडादेश को बरकरार रखने के लिए उसकी गवाही पर भरोसा करना असुरक्षित पाते हैं।

48- तदनुसार, हम शेष अपीलार्थी संख्या 1, 4 और 5 के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को **अपास्त** करते हैं।

49- आपराधिक अपील केवल अपीलार्थी संख्या 1, 4 और 5, अर्थात् **जराफत, महबूब और ममनून** के संबंध में **स्वीकार** की जाती है।

50- उपरोक्त अपीलार्थी जमानत पर हैं। उनके जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं और प्रतिभू उन्मोचित किए जाते हैं। उन्हें आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

51- कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस करे और इस निर्णय की सूचना विचारण न्यायालय को भी दे।

3 फरवरी, 2026

अभिषेक

(न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।